CHENNAI		
8.	New Port at Ennore	593.90
9.	Further Extension of Container Terminal	52.10
VISAKHAPATNAM		
10.	LPG jetty in Outer Harbour-	24.12
11.	Multipurpose Cargo berth in Outer Harbour.	37.70
PARADIP		
12.	Mechanised Coal handling facilities.	587.41

कांडला पत्तन के विस्तार के लिए योजना

880. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कांडला पत्तन न्यास के विस्तार और गोदियों के निर्माण के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उपरोक्त पत्तन की किन-किन योजनाओं और विस्तार के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है;

(ग) क्या कतिपय परियोजनाएं मंजूरी के लिए सरकार के पास लम्बित/विचाराधीन हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और वे परियोजनाएं कब से लम्बित/विचाराधीन हैं;

(ङ) इनकी अनुमानित लागत कितनी है;

(च) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है; और

(छ) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी०जी० वेंकटरामन): (क) जी हां।

(ख) कांडला पत्तन में कार्यान्वित की जा रही इन परियोजनाओं की सूची जिनकी लागत 5 करोड़ रु० अथवा उससे अधिक है:

क्रम सं०	पत्तन/परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	संस्वीकृति की तारीख	पूरा होने की अनुमानित तारीख
1	2	3	4	5
कांडला				
1.	तीसरी तेल जैटी का निर्माण	19.67 (संशोधित 29.8)	15.1.92	31.3.98
2.	8वीं सामान्य कार्गो बर्थ का निर्माण	18.82 (संशोधित 49.94)	9.6.94	31.8.99
3.	सभी उपकरणों आदि के साथ 66 कि०वा०/11 कि०वा० के विद्युत उपकेन्द्र की व्यवस्था	15.74	12.7.94	मार्च, 98
4.	4 विद्युत व्हार्फ क्रेनों की खरीद	21.19	29.3.95	28.4.98
5.	चौथी तेल जैटी का निर्माण	25.12	13.2.96	12.2.2000

(ग) से (ङ) 150.00 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से ह्यपर निकर्षक कच्छ वल्लभ को बदलने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(च) और (छ) संबंधित औपचारिकताओं के पूरे होते ही प्रस्ताव को संस्वीकृति दे दी जाएगी।

Report on the performance of Indian Shipping Industry

881. SHRI AKHILESH DAS: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the D.G. of Shipping Mr. Michael Pinto is reported to have said that Indian Shipping Industry's performance had been uneven for a very long time;

(b) if so, whether a report is being finalised on a major new shipping policy covering import and financing regulations for the purchase of new ships; and

(c) if so, the details in this regard; and by when Government propose to bring out this report?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T.G. VENKATRAMAN): (a) to (c) No, Sir. In order to consider the issues raised by the shipping industry from time to time to formulate a National Shipping Policy, a Committee under the Chairmanship of Director General of Shipping has been formed in March, 1997. The Committee is likely to submit its report by end July, 1997.

Port in West Godavari District in Andhra Pradesh

882. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government have received a specific proposal for a Rice/Food Grain Port in West Godavari district, Andhra Pradesh;

(b) if [illegible] full details [illegible];

(c) whether the proposal has been made by an individual or organisations;

(d) the details of the proposes including name;

(e) whether any attempt has been made to invite discussions on this proposal; and

(f) if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T.G. VENKATRAMAN): (a) and (b) Yes, Sir. A proposal has been received for development of a dedicated Rice/Grain Port at Narsapur in West Godavari District in Andhra Pradesh with the suggestion that the area is a rich producer of rice and can furnish sufficient cargo for successful operation of a dedicated Rice/ Grain Port.

(c) and (d) The proposal is from Dr. P. Pulla Rao of West Godavari District, Andhra Pradesh and has been forwarded through some Members of Parliament.

(e) and (f) The matter has been examined. Since Narsapur is a minor port, the responsibility for its development lies with the State Government of Andhra Pradesh.

सड़क परिवहन की मांग में वार्षिक वृद्धि

883. श्री राम जेठमलानी:
प्रो० राम कापसे:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आगामी वर्षों के दौरान देश में सड़क परिवहन की मांग में 12 से 15 प्रतिशत तक वार्षिक वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि बढ़ती हुई मांग को देखते हुए सरकार ने सड़क मार्ग परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की [illegible] के लिए [illegible] अड़चनों को अब तक दर